Supreme Court had directed that pending finalisation of Coastal Zone Management Plans (CZMPs), the interim orders passed by the Hon'ble Court on 12th December, 1994 and 9th March, 1995 shall continue to operate. The interim order dated 12th December, 1994 had directed all the coastal States/Union Territories not to permit the setting up of any industry or construction of any type in the areas at least upto 500 metres from the sea water at the maximum High Tide Line. Subsequently in another interim order dated 9th March, 1995, the Court modified it's order of 12th December, 1994 and directed that all the restrictions and prohibitions regarding construction and setting up of industries or for any other purposes contained in the Notification issued by the Minstry of Environment and Forests of February 19, 1991 and the amendment dated August 16, 1994 shall be meticulously followed by all the concerned States. The Hon'ble Court also directed all the coastal tates/ Union Territories to file the complete Coastal Zone Management Plans with the Central Government by June, 30, 1996. The Central Government shall finalise and approve the plans with or without modifications within three months thereafter. Necessary steps have been initiated to comply with the directions of the Supreme Court.

प्राकृतिक विपदाओं के पीड़ितों को वित्तीय सहायता

*329. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या गत वर्ष भारी वर्षा और बाढ़ के कारण विभिन्न राज्यों में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के आश्रितों को प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार, राज्य सरकारों की ओर से दी जाने वाली राहत-सहायता राशि के अतिरिक्त पचास हजार रुपए की राशि अदा की गई है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में मृत व्यक्तियों की जिला-वार संख्या कितनी-कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिनके आश्रितों को उक्त राहत-राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) पिछले वर्ष के दौरान हुई भारी वर्षा तथा बाढ़ के परिणामस्वारूप सभी मृतकों के परिवारों को 50,000 रुपए की दर से वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में से निधियां निर्मुक्त की गई थीं।

हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले वर्ष भारी वर्षा तथा बाढ़ के परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न जिलों में जितने लोगों की मृत्यु हुई, उनकी संख्या इस प्रकार है:—

1. कांगड़ा	17
2. शिमला	20
3. मण्डी	9
4. सोलन	5
5. सिरमौर	7
6. बिलासपुर	2
7. कुल्लू	43
8. हमीरपुर	1
9. उना	3
10. चम्बा	36
11. किन्नौर	4
12. लाहौल और स्पीति	2
कुल	149

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सभी मृतकों के मामलों में सहायता राशि वितरित कर दी गई है।

Mother tongue as Medium of teaching

*330. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any guidelines regarding introduction of mother tongue as the medium of teaching in primary schools;